होते हुए भी पप्नकलां परिषद में कुछ सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव है। पप्नकलां परिसर से संबंधित योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि 1983 से पंजीकृत समितियों की भूमि की आवश्यकता कब तक पूरी कर दी जायेगी।

Production of Kharif and Rabi crops

1339. SHRI RAM • JETHMALANI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a record production of Kharif crop in 1988 and that of Rabi in 1989 in the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is also a fact that procurement of rice and wheat has been less in comparison to the last year's procurement;

(d) if so the quantity of this procurement and how far it is less in .comparision to the last year's procurement; ana"

(e) whether Government consider the support price fixation policy of foodgrains, as main cause responsible for the less procurement; if so, whether Government propose to bring a change in the policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) and (b) Yes, Sir. On the basis of the available information from the States so far, production of Kharif foodgrains in 1988 and that of Rabi in 1989 is expected to be at the record levels of 97 and 75 million tonnes **respectively.**

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) No Sir.

परती जमीन को उपजाऊ जमीन बनाने के लिए प्रयोग

1340. श्री राम जेठमलानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा किये गए अनुसंधान के आधार पर परती भूमि को उपजाऊ बनाने के सफल प्रयोग किये गये हैं जिससे कि असिंचित भूमि से अधिकतम उपज प्राप्त करके वर्तमान औसत उपज को बढ़ाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने किसानों को इन प्रयोगों से अवगत कराने के लिए कोई व्यवस्था की है जिससे कि वे इन तरीकों का इस्तेमाल करके देश में उत्पादन वृद्धि कर सकें ;

(घ) क्या इन तरीकों को देश में क्रियान्वित किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में क्रियान्वित किये गये और कब से ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कार्य करने वाले कृषि अनुसंधान संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने घटिया भूमियों तथा

असिंचित भूमियों की उत्पादकता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। इन विकसित की गई प्रौद्योगिकियों में ये शामिल हैं (i) लवण प्रभावित भूमियों के सुधार के लिये प्रौद्योगिकी (ii) विभिन्न भूमि क्षमता एककों के तहत आने वाली भूमियों की उत्पादकता में सुधार के लिए संरक्षित खेती तथा (iii) बारानी भूमियों के लिए उन्नत बारानी प्रौद्योगिकी।

(ग)से (च) विभिन्न राज्य सरकारों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि विस्तार प्रणाली से माध्यम से संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। किसान मेलों, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाएं तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थान इन प्रौद्योगिकियों के प्रथम स्तर का प्रदर्शन करता है। ये संस्थान नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकियों के बारे में विस्तार कार्मिकों को भी प्रशिक्षित करते हैं।

किसानों को जानकारी देने के लिए भूमि संरक्षण, प्रबन्ध तथा सुधार से संबंधित विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा पूरे देश में उपरोक्त कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पूरे देश में आवश्यकता पर आधारित मृदा संरक्षण उपायों को अमल में लाया जा रहा है। भारत सरकार ने भी 500—1125 मि. मी. के बीच वर्षा वाले तथा 30% से कम सिंचाई वाले 16 राज्यों के 99 जिलों में जुलाई, 1986 से बारानी कृषि के लिए एक राष्ट्रीय जलसंभर विकास कार्यक्रम शुरू किया था। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में भूमि सुधार तथा विकास निगमों की स्थापना की गई है। करीब 4 लाख हेक्टेयर क्षारीय भूमियों का सुधार किया गया है तथा उसमें फसलें उगाई जा रही हैं।

Short term loans to States for k.harif seasons

1341.. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government had issued short term loans to States for the purchase and distribution of agricultural inputs during the kharif sea-son;

(b) if so, the loans issued and the amount distributed among the States;

(c) the amount provided to Madhya Pradesh for the said purpose; and

(d) to what extent it has helped the farmers?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHY AM LAL YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) A statement indicating the amount of short-term loans sanctioned to States for Kharif, 89 season is attached. (See below)

(c) An amount of Rs. 7.75 crores has been provided to Madhya Pradesh as short-term loan for Kharif, 1989 season.

(d)The short term loan sanctioned to States is to be utilised by institutional agencies mainly for timely purchase and distribution of agricultural inputs. Which thus helps farmers.